DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- राष्ट्रीय सहारा ------------------DATED

अमर उजाला
नई दिल्ली | शुक्रवार, 22 जुलाई 2022

# मेयर सम्मेलन में सीएम का क्या काम : LG

## केजरीवाल को सिंगापुर जाने की नहीं दी इजाजत

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर सम्मेलन में जाने की अनुमति मांगे जाने के सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। प्रस्ताव रद्द करने के साथ ही उप-राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि सिंगापुर में एक अगस्त को प्रस्तावित वर्ल्ड सिटी सम्मेलन महापौरों के लिए हैं। इस सम्मेलन में एक मुख्यमंत्री का भाग लेना ठीक नहीं होगा।

उप-राज्यपाल ने यह भी कहा है कि मेयरों में सम्मेलन में मुख्यमंत्री के शामिल होने से गलत नजीर बनेगी। उधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के लिए राजनीतिक अनुमति मांगने के वास्ते अब सीधे विदेश मंत्रालय का रुख करेगी।

**आमने-सामने**

■ **सिंगापुर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति मांगेंगे : सिसोदिया**

दरअसल मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में जाने के लिए उप-राज्यपाल से अनुमति मांगी थी। सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव लौटाने के साथ ही उप-राज्यपाल ने तर्क दिया है कि सिंगापुर सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इन पहलुओं पर दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) जैसे निकाय काम करते हैं। उप-राज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नही हैं और एक मुख्यमंत्री के लिए इस सम्मेलन में भाग लेना अनुचित होगा।

# एलजी ने सीएम की सिंगापुर यात्रा की फाइल लौटाई

## केजरीवाल बोले...दौरे पर जाएंगे, उपराज्यपाल ने कहा- मेयर सम्मेलन में सीएम का शामिल होना उचित नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

**नई दिल्ली।** उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे से जुड़ी फाइल बृहस्पतिवार को लौटा दी। उन्होंने सलाह दी, मेयर सम्मेलन में मुख्यमंत्री का शामिल होना उचित नहीं है। वहीं, केजरीवाल ने कहा, वह सिंगापुर जरूर जाएंगे। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यात्रा को मंजूरी देने में बाधा पहुंचा रही है।

उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, 'विश्व शहर शिखर सम्मेलन' पहली नजर में मेयर सम्मेलन लग रहा है, जो किसी मुख्यमंत्री की उपस्थिति के अनुरूप नहीं है। सम्मेलन का विषय भी सीधे दिल्ली सरकार से जुड़ा नहीं है। लिहाजा सीएम का शामिल होना अनुचित और गलत परंपरा की शुरुआत होगी। सूत्रों के अनुसार, फाइल लौटाने से पहले उपराज्यपाल ने सम्मेलन की प्रकृति व निमंत्रित लोगों की प्रोफाइल का अध्ययन किया है। जहां तक स्मार्ट सिटी वर्कशॉप का विषय है, दिल्ली में इसका संचालन नई दिल्ली नगरपालिका परिषद करती है। सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल हैं, जो काम एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए के हैं।



### 7 जून को भेजी थी फाइल

सिंगापुर में 31 जुलाई से तीन अगस्त तक सम्मेलन होना है। सात जून को दिल्ली सरकार ने फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजी थी। उपराज्यपाल ने करीब डेढ़ महीने बाद मुख्यमंत्री को सम्मेलन में शामिल न होने की सलाह दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोक को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन किया जाएगा।

>> फाइल रोकना राजनीति से प्रेरित : पेज 2

**सियासत**

एलजी के सिंगापुर दौरे की फाइल लौटाने के बाद सिसोदिया ने कहा

# सीएम की सिंगापुर यात्रा की फाइल रोकना राजनीति से प्रेरित

अमर उजाला ब्यूरो

**नई दिल्ली।** एलजी द्वारा सीएम के सिंगापुर दौरे की फाइल लौटाने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी आदि के क्षेत्र में शानदार काम किया है। इसे देखते हुए 'विश्व शहर शिखर सम्मेलन' में दुनिया भर के विषय विशेषज्ञ, शहरी मामलों के विशेषज्ञ, मेयर और दूसरे नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन एलजी ने मंजूरी नहीं दी।

सिसोदिया ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को सम्मेलन में बताना है कि हम अपने शहरों को किस तरह से बेहतरीन, रहने के ज्यादा अनुकूल और सक्षम बना सकते हैं। इस तरह दुनिया भर के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय राजधानी में लागू की जा रहीं नीतियों और सुधारों के बारे में जानने और सीखने में रुचि रखते हैं। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने करीब डेढ़ महीने तक फाइल रखने के बाद मुख्यमंत्री जी को समिट में शामिल नहीं होने की सलाह दे रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाते हैं, तो दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन आदि के मॉडल के बारे में चर्चा होगी और सभी लोग यह जानते है कि देश के बाहर ऐसे किसी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, एक निर्वाचित प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है।

सिसोदिया ने कहा कि यह सच नहीं है कि इस समिट में सिर्फ मेयर शामिल हो सकते हैं। सम्मेलन के कई संस्करणों में भारत सहित विभिन्न देशों के कई मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हुए हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसी सम्मेलन में शामिल हुए थे। मास्को, रूस के उपमुख्यमंत्री ईलया कुजमिन ने भी 2019 में इस समिट में हिस्सा लिया और इस साल भी इंडोनेशिया की मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड क्रिएटिव इकॉनमी सैनडिआगा उनो भी सम्मलेन में हिस्सा ले रही है।

### केजरीवाल से डरते हैं मोदी : आतिशी



**नई दिल्ली।** आप विधायक आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से नफरत के कारण प्रधानमंत्री और भाजपा भारत के गर्व के बारे में भूल गए हैं। केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिंगापुर में केजरीवाल की वाहवाही हो गई तो वह और भी बड़े नेता बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल निरंतर मोदी को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि केजरीवाल उनके विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

### ऐसे तो पीएम भी नहीं कर सकेंगे विदेश का दौरा



सीएम केजरीवाल ने कहा कि मानव जीवन को संविधान में दी गई तीन सूचियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में हर सांविधानिक अथॉरिटी का दौरा इस आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा विषय उस अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह सियासी गतिरोध पैदा करेगी। इस आधार पर न तो कोई मुख्यमंत्री किसी देश का दौरा कर पाएगा और न ही प्रधानमंत्री। वजह यह कि अपने अधिकांश दौरों में प्रधानमंत्री उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं, जो राज्य सूची में आते हैं। केजरीवाल के मुताबिक, यह सिर्फ मेयर का सम्मेलन नहीं है। इसमें मेयर, सिटी लीडर्स, विषय विशेषज्ञ समेत दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं। सिंगापुर सरकार ने उनको दुनिया भर के शहरों के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA | नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 22 जुलाई 2022 DATED----------

# सिंगापुर पर दिल्ली में बिगड़ी बात

File Photo

सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह उपराज्यपाल से विनम्रतापूर्वक मतभेद रखते हुए यात्रा जारी रखने का प्रयास करेंगे

## फाइल लौटाकर बोले उपराज्यपाल, सीएम के लायक नहीं यह प्रोग्राम

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

**1 अगस्त** को सिंगापुर में होने जा रही वर्ल्ड सिटीज समिट में हिस्सा लेने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने की इजाजत देने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस के बीच चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सूत्रों से पता चला है कि एलजी ने सीएम की प्रस्तावित विदेश यात्रा की फाइल को बिना इजाजत दिए वापस लौटाते हुए उन्हें सलाह दी है कि सीएम को इस समिट में नहीं जाना चाहिए। एलजी ने कहा है कि शुरुआती तौर पर देखने में लग रहा है कि सिंगापुर में होने जा रही आठवीं वर्ल्ड सिटी समिट और मेयर्स फोरम दुनियाभर के मेयरों की एक कॉन्फ्रेंस है और इसलिए एक मुख्यमंत्री का उसमें शामिल होना उचित नहीं है और ना ही ये सीएम को शोभा देता है। सूत्रों ने बताया कि फोरम के स्वरूप और उसमें जिन विषयों पर चर्चा होनी है, उन विषयों के साथ-साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे अन्य अतिथियों के प्रोफाइल का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद एलजी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि कॉन्फ्रेंस में मूलतः शहरी प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के संदर्भ में ये विषय दिल्ली सरकार से इतर एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए जैसी सिविक एजेंसियों के कार्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं। एलजी ने खासतौर से इस बात का भी जिक्र किया है कि कॉन्फ्रेंस की थीम से जुड़े विषयों पर केवल दिल्ली सरकार का एकाधिकार नहीं है। ऐसे में सीएम का इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना सही नहीं होगा।

1 अगस्त को सिंगापुर में होने जा रही वर्ल्ड सिटीज समिट

सूत्रों के मुताबिक, एलजी ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तो मुख्य रूप से एनडीएमसी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का शामिल होना एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।

## CM ने नहीं मानी एलजी की सलाह, विदेश मंत्रालय से मांगेंगे इजाजत

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

- सिसोदिया का आरोप, ओछी राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं
- दिल्ली में हो रहे काम से विदेश में भारत की साख बनती है: डिप्टी सीएम

**सिंगापुर में** होने वाली समिट में हिस्सा नहीं लेने की एलजी की सलाह को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि वह तय कार्यक्रम के अनुसार सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे और मंजूरी लेने के लिए अब विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे।

सीएम को लौटाई गई फाइल पर एलजी की नोटिंग का जवाब देते हुए सीएम ने लिखा है कि एलजी की सलाह पर गौर करने के बाद वह इन कारणों से उनके साथ मतभेद रखते हैं। सीएम ने बिंदुवार एलजी के एक-एक तर्क का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह केवल मेयरों का सम्मेलन नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया के तमाम बड़े शहरों के कई नेता और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं और सिंगापुर की सरकार ने खुद उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया है।

सीएम ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में प्रशासन के दिल्ली मॉडल, खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन के क्षेत्र में किए गए हमारे काम की चर्चा हो रही है और उसे मान्यता दी जा रही है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दुनिया के तमाम बड़े शहरों के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण का दौरा इसी आधार पर तय किया जाएगा कि उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं, तो एक अजीब स्थिति और व्यावहारिक गतिरोध पैदा हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अधिकांश यात्राओं में वह उन विषयों पर चर्चा करते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि राज्यों की सूची में आते हैं। ऐसे तो कोई सीएम दुनिया में कहीं का भी दौरा नहीं कर पाएगा। मैं एलजी से विनम्रतापूर्वक मतभेद रखते हुए यात्रा को जारी रखने का प्रयास करूंगा और राजनीतिक मंजूरी लेने के लिए केंद्र के पास आवेदन करूंगा।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले डेढ़-दो महीने से एलजी साहब फाइल लेकर बैठे थे और अब उन्होंने वही लिखकर भेजा है, जो बीजेपी के नेता कह रहे थे। ओछी राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं।

**कौन लेगा कांग्रेस की जगह, आप या टीएमसी?**
ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, दोनों अपने-अपने राज्यों में बीजेपी को बुरी तरह से हरा चुके हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा? **पढ़ें और सुनें सिर्फ Navbharatgold.com पर...**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS 8 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

# एलजी ने केजरीवाल को सिंगापुर जाने की नहीं दी अनुमति

एलजी वीके सक्सेना

- कहा, प्रथम दृष्टया यह सम्मेलन मेयरों का है, इसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना उचित नहीं
- डब्ल्यूसीएस स्मार्ट सिटी वर्कशाप का विषय भी दिल्ली में एनडीएमसी से संबंधित

अरविंद केजरीवाल

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर सियासी रार बढ़ती ही जा रही है। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इस दौरे से संबंधित प्रस्ताव की फाइल को लौटा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आठवीं 'वर्ल्ड सिटी समिट' और डब्ल्यूसीएस मेयर्स फोरम में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सम्मेलन मेयरों का है, जहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति उचित नहीं है।

राजनिवास से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने सम्मेलन का स्वरूप, उसमें शामिल होने वाले लोगों की प्रोफाइल एवं सम्मेलन को लेकर विचार-विमर्श किया। इसमें पाया कि यह सम्मेलन शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए है। इनसे संबंधित कार्य दिल्ली सरकार के अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों जैसे एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और डीडीए द्वारा किए जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए इस सम्मेलन में शामिल होना उचित नहीं होगा। डब्ल्यूसीएस स्मार्ट सिटी वर्कशाप का विषय भी दिल्ली में एनडीएमसी से संबंधित है। ऐसे में इस तरह के सम्मेलन में मुख्यमंत्री का शामिल होना एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी।

**उपराज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री ने जताई असहमति:** उपराज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मेयरों के साथ ही यह सिटी लीडर्स, नालेज एक्सपर्ट्स आदि का भी सम्मेलन है। सिंगापुर सरकार ने उन्हें दुनिया भर के नेताओं के सामने दिल्ली माडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम सभी को इसके लिए खुशी मनानी चाहिए और इसे बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मानव जीवन को संविधान में दी गई तीन सूचियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे देश में प्रत्येक संवैधानिक अथारिटी का दौरा इस आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा विषय उस अथारिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह एक अजीब स्थिति है। इससे राजनीतिक गतिरोध पैदा होगा।

इस आधार पर न तो कोई मुख्यमंत्री किसी देश का दौरा कर पाएंगे और न ही प्रधानमंत्री कहीं जा सकेंगे, क्योंकि अपने अधिकांश दौरों में वह उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं, जो राज्य सूची में आते हैं, न कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

संबंधित खबरें >> पेज 8

# एलजी का निर्णय राजनीति से प्रेरित : सिसोदिया

## सिंगापुर यात्रा का मामला

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली:** उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल के निर्णय पर कड़ा विरोध जताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल का यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इसे देखते हुए अब मुख्यमंत्री राजनीतिक मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह निर्णय राजनीति का शिकार नहीं होगा।

उपमुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के क्षेत्र में शानदार काम किया गया है। इसे देखते हुए कि 'वर्ल्ड सिटी समिट' में जहां दुनिया भर के गवर्नेंस एक्सपर्ट, अर्बन एक्सपर्ट और नेता शामिल हो रहे हैं। सिंगापुर की सरकार ने केजरीवाल को आमंत्रित करते हुए कहा है कि उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे हम अपने शहरों को और अधिक रहने योग्य बना सकते हैं। दुनिया भर के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री से राजधानी में लागू की जा रही नीतियों और सुधारों के बारे में जानने और सीखने में रुचि रखते हैं। देश के बाहर ऐसे किसी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया को री-ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सम्मेलन के पिछले कई संस्करणों में भारत सहित विभिन्न देशों के कई मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हुए हैं। 2018 में इसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए थे। इस सारे प्रकरण पर आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और भाजपा को सीएम अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है कि वह भारत के गर्व के बारे में भी भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिंगापुर में केजरीवाल की वाहवाही हो गई तो वह और भी बड़े नेता बन जाएंगे।

### विदेश मंत्रालय को मिला सीएम केजरीवाल का आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा को लेकर राजनीतिक मंजूरी के संबंध में एक आग्रह प्राप्त हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि मंत्रालय के पोर्टल पर इसके लिए अनुरोध मिला है। इसके लिए एक व्यवस्था निर्धारित है। ऐसा माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय संभवत: केजरीवाल को सिंगापुर जाने की मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि यह आग्रह सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRES

the pioneer

NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI | FRIDAY | JULY 22, 2022

# After LG veto, Kejriwal sends online request to MEA for foreign trip nod

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal approached the Ministry of External Affairs on Thursday for visiting Singapore to attend the World Cities Summit hours after Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena turned down his request seeking clearance for the travel.

"I do not agree with the advice of the Lieutenant Governor," said Kejriwal, adding that if one goes by his logic, then the Prime Minister will also not be able to go anywhere".

The AAP Government shared Kejriwal's reply and the LG's letter on Twitter on Thursday. After the LG's rejection, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia said they will directly go to the MEA to seek clearance for Kejriwal.

Later in the evening, the MEA confirmed it has received request for political clearance for Kejriwal's visit to Singapore. MEA spokesperson Arindam Bagchi said the "entry" for the clearance was made on the Ministry's dedicated online portal that receives such requests.

"I was just informed that an entry has been made in the Ministry's online portal. There is a system to request for political clearance," he said while replying to a question on the issue at his weekly media briefing.

*Continued on Page 2*

## After LG veto, Kejriwal sends online request to MEA for...

**From Page 1**

In October 2019, Kejriwal wanted to visit Denmark to address a C-40 World Mayors' Summit, but his request was turned down by the MEA saying his visit there as a speaker at a panel discussion did not commensurate with the level of participation from other countries. Earlier, rejecting the Delhi Chief Minister's request to visit Singapore, the LG advised Kejriwal to not attend the World Cities Summit in Singapore next month since it is a conference of mayors and won't be befitting for a Chief Minister to attend it.

"The subjects that are being deliberated in this conference cover different aspects of urban governance, which in the case of Delhi are addressed by diverse bodies ranging from the New Delhi Municipal Committee (NDMC), Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA) in addition to the Delhi Government. The Delhi Government does not have exclusive domain over these issues corresponding with the theme of the conference. A WCS Smart Cities workshop is also being organised as a part of the summit. In Delhi, the Smart Cities Project is being anchored by the NDMC. In such a context, it is not advisable for a CM to be attending such a conference," the LG said in his letter to Kejriwal.

Responding to the permission denial in a letter, Kejriwal wrote, "I humbly beg to differ with the advice of the LG. If the visit of each constitutional authority in our country were to be decided on the basis of what subjects fall within the jurisdiction of that authority, it would create a funny situation and practical logjam. Then the Prime Minister would not be able to go anywhere because in most of his visits, he also discusses subjects which fall in the State list and do not fall in his jurisdiction," the letter added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times DATED 22/7/2022

# Kejriwal can't visit S'pore, says Delhi LG

Sweta Goswami
letters@hindustantimes.com

EVENT MEANT FOR MAYORS DOESN'T BEFIT CM, SAYS LG; KEJRIWAL SAYS HE WILL NOW SEEK APPROVAL FROM THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS FOR THE VISIT

**NEW DELHI:** Delhi lieutenant governor VK Saxena on Thursday rejected the Delhi government's proposal for chief minister Arvind Kejriwal's visit to Singapore for the 'World Cities Summit' scheduled for next month, saying that the event is meant for mayors, and it is not befitting for a chief minister to attend it, a move that is likely to further the rift between the two.

Kejriwal said that he will now seek approval from the ministry of external affairs for the same.

"Having studied the nature of the forum and the other attendees, it must be noted that on a prima facie basis this is a conference of mayors of various cities. The subjects that are being deliberated in this conference cover different aspects of urban governance, which in the case of Delhi are addressed by diverse bodies ranging from the New Delhi Municipal Council (NDMC), Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA), in addition to the Delhi government," the note by Saxena, seen by HT, said. The LG further said that the Delhi government "does not have exclusive domain" over the issues corresponding with the theme of the conference.

"A WCS Smart Cities workshop is also being organised as a part of the Summit. In Delhi, the Smart Cities project is being anchored by the NDMC. In such context, it is not advisable for a chief minister to be attending such a conference," Saxena wrote. Responding to Saxena's note, the chief minister said he differed with the LG's advice. "I differ with the advice of the Hon'ble Lieutenant Governor.

continued on →11

## KEJRIWAL, DELHI LG

We will go ahead with the visit and apply for political clearance from the central government," he said in a letter on Thursday.

If every visit by a constitutional authority in the country were to be decided on the basis of what subjects fall within it's jurisdiction, a "funny situation" would be created, Kejriwal said.

"If the visit of each constitutional authority in our country were to be decided on the basis of what subjects fall within the jurisdiction of that authority, it would create a funny situation and practical logjam. Then the Prime Minister would not be able to go anywhere because during most of his visits, he also discusses subjects which fall in state list and do not fall in his jurisdiction. Then no CM would ever be able to make any visit anywhere in the world," Kejriwal's letter said.

Minutes after the LG's office revealed that Saxena had advised against Kejriwal's Singapore visit, deputy chief minister Manish Sisodia said in a press briefing that Kejriwal will now apply to the MEA for political clearance.

"While inviting CM Kejriwal, the High Commissioner of Singapore Simon Wong stated - 'your insights will enrich our discussion on how we can make our cities more sustainable and liveable'. Kejriwal just wanted to showcase Delhi in a global platform. He wanted to show how a city as big as Delhi managed to improve its health and education system while also offering revolutionary schemes such as free transport for women and free water and power. But the LG, after sitting on the file for one-and-half months has now returned the file advising Kejriwal not to attend the conference stating it is typically for mayors," Sisodia said.

Following Sisodia's presser, the MEA said it received a request for approval from the Delhi chief minister for his Singapore visit to attend a summit on Thursday (July 21).

"The online portal for political clearance on our website has just received an entry in their portal regarding the Delhi CM's visit to Singapore to attend the 'Eighth World Cities Summit and WCS Mayors Forum'. The decision will be taken following due process," MEA spokesperson Arindam Bagchi said on the sidelines of a press briefing.

People in the external affairs ministry familiar with the matter said there was a grey area regarding the clearance required for such a visit. If an application for political clearance for a foreign visit is made without the requisite approvals and formalities, it is unlikely to be cleared, the people said.

Requests for overseas visits by CMs are first sent to the MEA for political clearance and also the home ministry for FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) clearance, after which they are sent to the Cabinet Secretariat informing it about the proposed travel. But Kejriwal's office sent the file for his Singapore visit to Delhi Lieutenant Governor VK Saxena for his approval.

When asked why the chief minister's office sent the file to the LG instead of the MEA, Sisodia said, "There is no other way. We have always done it this way."

A file for Kejriwal's Singapore visit was sent by the Delhi government to the LG office on June 7. The summit will take place in the first week of August. The High Commissioner of Singapore Simon Wong in June invited Kejriwal to the World Cities Summit. The Delhi chief minister has been asked to attend a programme on the first day.

In October 2019, chief minister Arvind Kejriwal wanted to visit Denmark to address a C-40 World Mayors' Summit, but his request was turned down by the MEA stating that his visit there as a speaker at a panel discussion was not commensurate with the level of participation from other countries.

Leader of the Opposition in the Delhi Assembly, Ramvir Singh Bidhuri welcomed the LG's decision. "The Mayor of Surat has also been called from India. When the chief minister of Delhi got an invitation to participate in this conference, he should have sent this invitation to the MCD at the same time because only the Mayor of Delhi could participate in it. Now that Special Officer Mr Ashwini Kumar is handling the work of the Mayor, he should accompany the Municipal Commissioner to attend this conference and go there and explain how the MCD overcomes the challenges of the city. Instead of doing so, Kejriwal decided to attend the summit himself only, which was unfair and meaningless," he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

हिन्दुस्तान

# 'हर हफ्ते सौ किलोमीटर मार्ग से कब्जे हटाएं'

निर्देश

**नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।** दिल्ली की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और सभी स्थानीय निकायों को मिलाकर बनाई गई टास्क फोर्स ने अधिकारियों को प्रति सप्ताह 100 किलोमीटर सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही एसटीफ की हर सप्ताह होने वाली बैठक में इस बाबत रिपोर्ट भी देने को कहा है। हर सप्ताह तय अतिक्रमण नहीं हटाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।

**निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए :** एसटीएफ की ओर से दिल्ली नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भले ही निगम एक हो गया हो, लेकिन जोन के अधिकारियों की जिम्मेदारियां अभी भी वहीं हैं। ऐसे में दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में यमुना खादर और प्रमुख सड़कों पर तेजी से अतिक्रमण और अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसटीएफ की बैठक की रिपोर्ट को एलजी कार्यालय में तलब किया जा रहा है, ऐसे में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में किसी प्रकार की चूक न हो।

**पहले तीन सौ किलोमीटर था लक्ष्य :** बता दें कि पहले सड़कों से अतिक्रमण हटाने का यह लक्ष्य तीन सौ किलोमीटर प्रतिमाह हुआ करता था। इसे अब बढ़ा दिया गया है। लक्ष्य को बढ़ाकर अब चार सौ किलोमीटर प्रतिमाह कर दिया गया है।

## मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट मांगी

दूसरी ओर दिल्ली में सील हो चुकी संपत्तियों को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी ने चिंता व्यक्त की है और इन संपत्तियों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बीते दिनों हुई एसटीएफ की बैठक में कहा गया है कि मॉनिटरिंग कमेटी को पता चला है कि जो संपत्तियां सील हैं, उनमें अब भी व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। उन्हें जल्द से जल्द बंद करने और ऐसे संपत्ति मालिकों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस बाबत मॉनिटरिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें मौजूदा समय में सील संपत्तियों की स्थिति को लेकर अधिकारी जानकारी देंगे।

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

# राजधानी में 76 प्रतिशत झाड़ियां लगाकर पूरा किया जाएगा पौधारोपण अभियान

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- जमीन की कमी और धूल प्रदूषण रोकना है इसकी बड़ी वजह
- 17 एजेंसियां पूरा करेंगी पौधारोपण, दोबारा निर्धारित किया गया लक्ष्य

इस साल राजधानी में सालाना पौधारोपण अभियान 76 प्रतिशत तक झाड़ियां लगाकर पूरा किया जाएगा। इसकी वजह पौधे लगाने के लिए भूमि की कमी एवं धूल प्रदूषण को रोकना है। अभियान की जिम्मेदारी 17 एजेंसियों को दी गई है, जिन्हें यह कार्य मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले पूरा करना है। सभी एजेंसियों को दिया गया लक्ष्य फिर से तय किया गया है।

वन विभाग के मुताबिक, 2022-23 में दिल्ली में 35.4 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य है। इसमें से 7.4 लाख पौधे और 27.4 लाख झाड़ियां हैं। 7.8 लाख पौधे मुफ्त बांटे जाएंगे। वन विभाग के अलावा इस कार्य में केंद्र और दिल्ली सरकार के 17 विभाग भी तय लक्ष्य को पूरा करेंगे। विभिन्न इलाकों में स्थित सरकार की 14 नर्सरियों से मुफ्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि पौधारोपण के लिए दिल्ली में जगह की कमी है। डीडीए से जगह उपलब्ध कराने को कहा गया है, लेकिन मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ लगातार बढ़ते धूल प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है और इसमें झाड़ियां खासी मददगार हो सकती हैं। जमीनी स्तर पर वनस्पति धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने में बेहतर है और पौधारोपण को भी अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। इसीलिए इस साल झाड़ियां ज्यादा लगाई जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि बड़े स्थानों पर जहां पेड़ लगाए जाते हैं, झाड़ियों को भी इस आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जमीनी या मध्य-स्तर की वनस्पतियों के बिना, अकेले पेड़ किसी क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को ज्यादा मजबूती प्रदान नहीं करेंगे।

**ये विभाग पूरा करेंगे अभियान:** डीडीए, एमसीडी, शिक्षा विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, टीपीडीडीएल, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, जल बोर्ड, उत्तर रेलवे, डीटीसी, पर्यावरण विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, JULY 22, 2022

# L-G rejects Kejriwal's Singapore visit proposal, he hits back, seeks MEA nod

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JULY 21

AFTER THE L-G returned the proposal on Chief Minister Arvind Kejriwal's foreign visit for a summit in Singapore, "advising" him not to go, the CM reiterated that it was not just a mayor's conference.

In a letter responding to the L-G's decision, Kejriwal wrote: "It is a conference of mayors, city leaders, knowledge experts etc. Singapore government has chosen to invite the CM of Delhi... Human life is not compartmentalised into subjects mentioned in the three lists of the Constitution. If the visit of each constitutional authority in our country were to be decided on the basis of what subjects fall within the jurisdiction of that authority, it would create a funny situation and practical logjam. Then the Prime Minister would not be able to go anywhere because in most of his visits, he also discusses subjects which fall in State list and do not fall in his jurisdiction."

Hitting out at the decision and calling it "mean politics", Deputy CM Manish Sisodia said Kejriwal did not agree with the L-G's "advice" and has written to the Ministry of External Affairs (MEA) for clearance. The summit will be held on August 3-4.

"The Delhi CM was invited to Singapore for World Cities Summit by the government. It was said urban experts, business, governance leaders were coming for it. The Singapore government has written — 'your insights will enrich our discussions on how we can make our cities more liveable and sustainable'," he said.

"Over the last 1.5-2 months, the file was with the L-G. Now he's written what BJP leaders were saying since yesterday, that this is a conference of mayors and doesn't cover subjects under ambit of GNCTD, so it is advised that the CM should not go for it," he added.

CM Arvind Kejriwal

Sources in the L-G office said the World Cities Summit prima facie seemed to be a conference of mayors and, and did not "befit attendance" by a CM. "Having carefully studied the nature of the forum and profile of other attendees, as also the subjects being deliberated upon at the conference, the L-G pointed out that the conference will be covering different aspects of urban governance which in the case of Delhi are addressed by diverse civic bodies ranging from the NDMC, MCD and DDA apart from the GNCTD," said a source. "The L-G underlined the fact that GNCTD does not have exclusive domain over issues corresponding with the theme of the conference and, hence, it will be inappropriate for a Chief Minister to be attending the same," the source said.

Sisodia said many things were to be discussed at the summit including Delhi's education system, health, electricity and public transportation: "The CM has written he does not agree with advice of the L-G. He has got the invitation to present liveable and sustainable model of Delhi before world leaders. If Singapore government or any other government has called Delhi government to present these things, how can anyone have a problem with it? This should be a matter of pride for the country. But such things are being done due to mean politics."

"The CM has now decided that he will apply for political clearance with the Ministry of External Affairs... We are confident and hopeful that the central government will also see his point and give clearance for the same, and that the Delhi model will be put forward in front of world leaders in Singapore," he added.

Sisodia said earlier too, CMs from India have gone for such summits, not just from Delhi but other states too.

The External Affairs Ministry, meanwhile, received a request for approval for Kejriwal's visit to Singapore. The ministry said an "entry" on its portal for political clearance had come in the morning. MEA spokesperson Arindam Bagchi said the decision will be taken following due process.

Delhi BJP chief Adesh Gupta meanwhile said: "Instead of politicising the issue of attending the mayors' meet in Singapore, Kejriwal should focus on resolving Delhi's problems."

In 2019, MEA had denied Kejriwal permission to attend the Copenhagen C40 World Mayors' Summit in Denmark. Former Delhi CM Sheila Dikshit had attended the same summit in 2007 in New York.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, JULY 22, 2022 -DATED----------

# LG 'advises' against S'pore 'mayors meet', CM seeks MEA's nod

Atul.Mathur@timesgroup.com

**'MAY NOT BE CLEARED'**

- Request seeking MEA's nod for CM Kejriwal's trip lacks approval from a 'competent authority', say central govt sources, adding the ministry is unlikely to clear the visit
- Though LG Saxena says 'it is not advisable for a CM to attend a conference of mayors', Kejriwal argues Singapore govt invited him to present the 'Delhi model' before the participants

**New Delhi:** Hours after lieutenant governor VK Saxena "advised" chief minister Arvind Kejriwal against attending a summit in Singapore, saying it was a "conference of mayors not befitting attendance by a chief minister", the latter said on Thursday he would "go ahead" with the visit and asked officials to apply for political clearance from the Centre.

Rejecting the LG's message that the Delhi government did not have "exclusive domain" over issues corresponding to the theme of the conference, Kejriwal said going by that logic, "the PM won't be able to go anywhere".

The MEA later confirmed it had received a request from the CM. However, spokesperson Arindam Bagchi didn't respond to queries about whether the visit would be approved or not.

▶Related report, P 13

# Subjects covered by civic bodies too: LG

## No Decision On Delhi Govt's Plea To MEA On S'pore Meet

Atul.Mathur@timesgroup.com

**New Delhi:** The foreign ministry on Thursday said an "entry" seeking clearance for CM Arvind Kejriwal's visit to Singapore was made on the ministry's dedicated online portal. However, government sources said the request lacked approval from the "competent authority" and that this meant the ministry was unlikely to clear the visit.

Kejriwal has been invited by the Singapore high commissioner for the 'Eighth World City Summit & WCS Mayors Forum' to be held from July 31 to August 3. The CM was likely to address the summit on August 1. Following a delay in getting an approval, he had written to the Prime Minister last Sunday saying that preventing a chief minister from attending such an event was "against the interests of the nation".

All chief ministers and ministers of union government and state governments have to inform the MEA and cabinet secretariat of any proposed foreign visit, official or private. According to officials, prior political clearance from the MEA and FCRA clearance are mandatory for such visits. Delhi being a union territory with a legislative assembly, all such files are routed to the MEA through the LG.

Rejecting Kejriwal's proposal, the LG said that the subjects that will be discussed at the conference cover different aspects of urban governance, which are handled by diverse civic bodies, including NDMC, MCD and DDA, apart from the Delhi government.

"The GNCTD does not have exclusive domain over the issues corresponding to the theme of the conference...It is not advisable for a chief minister to be attending such a conference," the LG said in his note.

Kejriwal, however, argued that it was not just a mayors' conference but will also be attended by city leaders and knowledge experts from across the world and the government of Singapore had chosen to invite the CM of Delhi to present the 'Delhi model' before them.

He added that if the visit of each constitutional authority in the country was to be decided on the basis of what subjects fall within the jurisdiction of that authority, it would create a "funny situation and a practical logam".

"Then the Prime Minister would not be able to go anywhere because in most of his visits, he also discusses subjects which fall in the state list and do not fall in his jurisdiction. Then no CM would ever be able to make any visit anywhere in the world," Kejriwal said in his note.

Addressing a press conference, deputy CM Manish Sisodia said that former Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu had participated in the same conference in 2018. Observing that the LG's advice was "motivated by dirty politics", Sisodia said he failed to understand how anyone can have a problem with the country getting praise on the global stage because of a state government's work. "This is a very mean form of politics being played out against us," he said.

This is not the first time that Kejriwal and his cabinet colleagues have been denied permission for a foreign visit to participate in a conference. The CM had to address the C40 Cities Climate Summit, held in Copenhagen in October 2019, via video conferencing after he was denied permission for a visit.

Deputy CM Manish Sisodia was denied permission twice – in August 2019 to participate in the World Education Conference in Moscow and in December 2018 to talk about the happiness curriculum in Austria. Former health minister Satyendar Jain's proposed visit to University of Melbourne and George Institute, Sydney, was rejected in November 2018.

**Instances of AAP ministers being refused permission to participate in world conferences**

**Oct 2019 | CM Arvind Kejriwal** refused political clearance to participate in C40 Cities Climate Summit in Copenhagen

**Aug 2019 |** Deputy CM Manish Sisodia denied permission to participate in World Education Conference in Moscow

**Dec 2018 |** Sisodia denied approval to talk about Happiness Curriculum in Austria

**Nov 2018 |** Former health minister Satyendar Jain denied permission to deliver a lecture on mohalla clinics at University of Melbourne and George Institute, Sydney

File photo

**When West Bengal CM Mamata Banerjee was not given clearance**

**Dec 2021 |** To attend a convention of Nepali Congress

**Oct 2021 |** World Peace Conference in Italy